PEACE LIBRARY
1291
27/3/08
NEW DELHI

बिजली और हम
(चर्चा आधारित पुस्तिका)

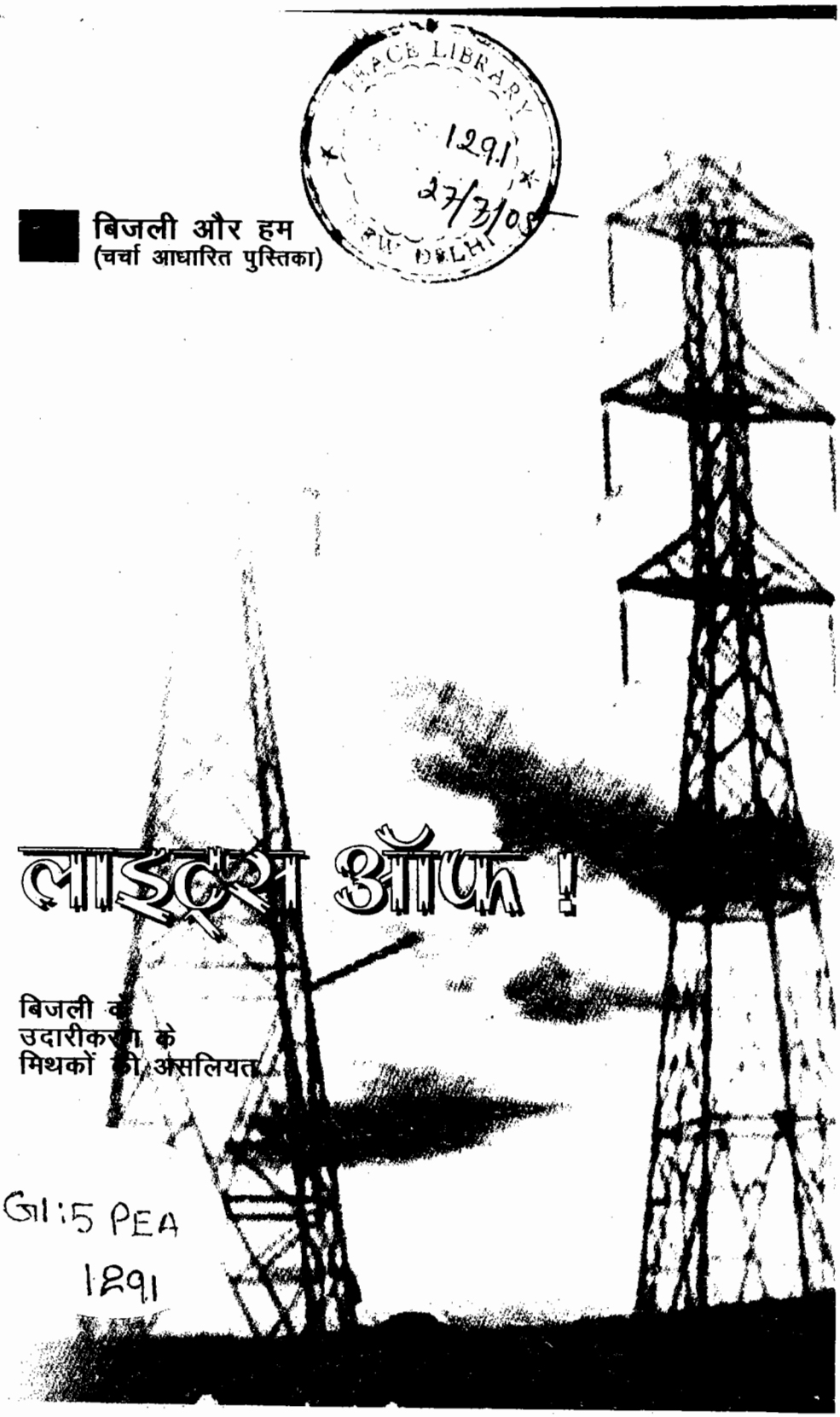

लाइट्स ऑफ !

बिजली के
उदारीकरण के
मिथकों की असलियत

G1:5 PEA
1291

कहां तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए
कहां मयस्सर नहीं चिराग हर शहर के लिए

– दुष्यंत कुमार

संपादक:
डैनियल सावेज़

संपादकीय सहयोग:
एंतोनिओ कामोना बाएज़
ओलिया कॉवेल
तातिआना रोआ एवेंदानो

हिंदी अनुवाद:
ईश मिश्रा

विषय वस्तु

संपादकीय 5
विद्युत उदारीकरण की विचारधारा 7
विद्युत उदारीकरण मिथकों की असलियत 9

मिथक 1: उदारीकरण के बाद बिजली क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि होगी 9

मिथक 2: उदारीकरण के बाद बिजली सस्ती होगी 15

मिथक 3: बिजली का उदारीकरण पर्यावरण के लिए लाभप्रद है 17

मिथक 4: सरकारें अपना रास्ता खुद चुन सकती हैं : निजीकरण और विनियंत्रण थोपा नहीं जाएगा 17

मिथक 5: बिजली का उदारीकरण जनतंत्र के लिए लाभप्रद 19

मिथक 6: निजीकरण और विनियंत्रण गरीबों के लिए लाभप्रद 24

उपयोगी वेबसाइट्स 31

ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट का प्रकाशन
पीस द्वारा जनहित में जारी

संपादकीय

सारी दुनिया में बिजली क्षेत्र का उदारीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और बहुआयामी विकास बैंक कॉरपोरेटी सुधार को दक्षता और आर्थिक विकास में विदेशी निवेश आकर्षित करने के माध्यम के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं और क्षेत्रीय अथवा भूमंडलीय व्यापार समझौतों की शर्तों से उत्पन्न परिस्थिति से निबटने के लिए दुनिया के ज्यादातर देश उदारीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। बिजली और समाज के इस पहले अंक का मकसद उदारीकरण के घोषित लाभों की जांच–पड़ताल एवं बिजली क्षेत्र के निजीकरण और विनियंत्रण के कुछ मिथकों की असलियत उजागर करना है।

बिजली बाजार के उदारीकरण का घोषित उद्देश्य बिजली की दरों में कमी और गुणवत्ता में सुधार के जरिए आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, लेकिन तथ्य इसके विपरीत हैं। पिछले पांच सालों में, न्यूजीलैंड से कैलिफोर्निया तक और भारत से ब्राजील तक बिजली गुल रहने से लोग त्राहि–त्राहि करने लगे हैं। बिजली की दरें आसमान छू रही हैं। इस पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और उदारीकरण का प्रतीक माना जाने वाला एनरॉन कॉरपोरेशन ध्वस्त हो गया है।

राष्ट्रीय सरकारों के सलाहकार के रूप में, परियोजना के विकासकर्ता के रूप में और विकास कार्यों के लिए कर्जदाता के रूप में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं क्षेत्रीय बैंक (एडीबी,एएफडीबी, आईएडीबी, ईबीआरडी) निजीकरण और विनियंत्रण की योजनाओं को लागू करने के लिए काफी समय से सक्रिय है। प्रायः कर्ज की शर्त के तहत् बिजली का निजीकरण जुड़ा होता है। यह बात सब देशों के लिए लागू है। दक्षिण के देशों में इन योजनाओं को गरीबी–उन्मूलन के माध्यम के रूप में पेश किया जाता है। उत्तर के देशों में उदारीकरण उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संधि (नाफ्टा) और यूरोपीय संघ की शर्तों के तहत् हो रहा है। विद्युत सेवाओं का उदारीकरण गैट्स समझौते के विस्तार का एक महत्वपूर्ण घटक है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के ढांचे के तहत इस पर वार्ताएं चल रही हैं। निजीकरण और विनियंत्रण के नतीजे सभी जगहों पर निराशाजनक हैं।

उदारीकरण की प्रक्रिया उपलब्ध विकल्पों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित न होकर विचारधारात्मक जड़ता और निहित स्वार्थों से प्रेरित है। जहां तक कार्यकुशलता का सवाल है, अभी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है जिससे पता चलता हो कि निजी क्षेत्र सरकार से बेहतर उत्पादक व प्रबंधक है। तथ्यपरक अध्ययनों से पता चलता है कि बिजली के सरकारी और निजी उपक्रमों की कार्यकुशलता में कोई फर्क नहीं है।

बिजली के उदारीकरण का मतलब है एक निर्णायक आर्थिक क्षेत्र पर से सार्वजनिक सत्ता के अधिकार और संप्रभुता की समाप्ति। सार्वजनिक संपत्तियों पर शक्तिशाली और अनुत्तरदायी बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशनों का आधिपत्य स्थापित होता जा रहा है।

सार्वजनिक सत्ता के एकाधिकार के नकारात्मक प्रभावों के दावे काफी कुछ विदेशी निजी कंपनियों के प्रचारतंत्र का परिणाम हैं। ये निजी कंपनियां बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण की सारी कड़ियों पर नियंत्रण करना चाहती हैं। ये कॉरपोरेशन सरकारों द्वारा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा दरों, आपूर्ति और पर्यावरणीय मानकों पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना चाहते हैं।

हो सकता है कि किसी विशिष्ट राष्ट्रीय संदर्भ में उदारीकरण से कुछ आर्थिक और सामाजिक फायदे हुए हों, लेकिन इसके कथित दूरगामी लाभों की बात तर्कसंगत नहीं है। घाटा देने वाली सरकारी सेवाओं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वामित्व से ये निर्णायक सेवाएं उत्तरदायित्व और जनतांत्रिक नियंत्रण से परे हो जाएंगी। आंख बंद कर उदारीकरण का जाप करने की बजाय नीति निर्माताओं को विद्युत क्षेत्र में सुधार के अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

पर्यावरण और समाज के संतुलन को बरकरार रखते हुए निर्मित बिजली की सुलभता एक मूलभूत अधिकार है। बिजली को व्यापारिक सामग्री बना देने से इसकी दर और आपूर्ति अनिश्चितता के भंवर में फंस जाएगी। यह बात इस लेख में वर्णित बहुत से असफल सुधारों के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। नवउदारवादी विद्युत सुधारों के हिमायतियों द्वारा फैलाए गए मिथकों का एक प्रगतिशील परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र विश्लेषण जरूरी है। विश्व–व्यापी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय अस्थिरता और कृत्रिम बिजली संकट के लिए मुक्त–बाजारवादी ही जिम्मेदार हैं।

विद्युत उदारीकरण की विचारधारा

पिछली पूरी शताब्दी तक बिजली का उत्पादन ऊर्ध्वाकार, समेकित जनसेवाओं के प्राधिकरण द्वारा होता रहा है। यही सुविधाओं का मालिक भी था और तीन चरणों उत्पादन, संचरण और वितरण में बिजली उत्पादन का कार्य संचालक भी। ज्यादातर जन सुविधाएं सरकारी एकाधिकार में थीं। 'पैमाने के अर्थशास्त्र' (बीर्ने और मुन : 2001) के तर्क पर आधारित ढांचा एक व्यापक, केंद्रीकृत अभियांत्रिकीय नेटवर्क के विकास को प्रोत्साहित करने वाला ढांचा है। बीसवीं सदी खत्म होते–होते नवउदारवादी प्रतिमान के उदय के साथ स्थिति में बुनियादी बदलाव आता गया।

1990 के दशक के मध्य से 2000 तक 30 से अधिक राष्ट्रीय, राज्य अथवा प्रांतीय सरकारें बिजली क्षेत्र में सुधार लागू कर चुकी थीं। (बेसेंट–जोन्स और तेनेबाउम : 2001) कुछ औद्योगिक देशों में, दक्षिण में इन सुधारों के लागू करने के काफी पहले ही बिजली बाजार और उससे जुड़े नियम–कानूनों का उदारीकरण हो चुका था। अमरीका ने अपने विद्युत क्षेत्र के विनियंत्रण की प्रक्रिया 1978 में पब्लिक यूटिलिटीज रेगुलेटरी एक्ट कानून के पारित होने के साथ ही शुरू कर दी थी। चिली (1982), न्यूज़ीलैंड (1987), नार्वे (1991) और अर्जेंटीना ने भी अमरीका का अनुसरण किया। विनियंत्रण के लिए भूमंडलीय दबाव 1989 में इंगलैंड में निजीकरण और विनियंत्रण की शुरूआत से बनना शुरू हुआ। (थॉमस : 2001) लैटिन अमरीका और एशिया बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। 1990 के दशक में लैटिन अमरीकी विद्युत क्षेत्र में कुल 78 खरब डॉलर का विदेशी निजी निवेश हुआ।

इस क्षेत्र की सरकारें पेंशन प्रणाली, दूरसंचार, पानी एवं अन्य मूलभूत सेवाओं के बाजारोन्मुख सुधारों समेत, व्यापक अर्थों में निजीकरण की हिमायती रही हैं। चिली की तानाशाही (1973–90) इस मामले में सबसे आगे थी। बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करके उसके निजीकरण की शुरूआत सबसे पहले चिली ने ही किया। पिछले एक दशक के अनियंत्रित और आक्रामक उदारीकरण के दौरान, पूरे लैटिन अमरीका में, सारी

सरकारी सार्वजनिक सुविधाओं – नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय उपक्रम सभी का पूरी तरह निजीकरण हो चुका है। (ईआईए–2002)।

एशिया में, सरकारें अभी विद्युत क्षेत्र के निजीकरण के मामले में लैटिन अमरीकी हद तक नहीं गई हैं। ये सार्वजनिक ग्रिड की बिजली के वितरण के लिए, ज्यादातर स्वतंत्र विद्युत प्रदाताओं (इंडिपेन्डेंट पॉवर प्रोवाइडर्स – आईपीपी) पर निर्भरता की नीति का पालन करती है। 1990 के दशक में एशिया के बिजली क्षेत्र में 93 खरब डॉलर का निजी निवेश हुआ। (ईआईए : 2002)। बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशनों की भूमिका बिजली के उत्पादन तक सीमित है। संचरण और वितरण पर सरकारों का नियंत्रण है। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी (आईईए) द्वारा 2001 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, 'विकसित' दुनिया में आईसीडी के सभी सदस्य औद्योगिक देश पहले से ही विद्युत क्षेत्र के सुधार में जुटे हुए हैं। 2006 तक ओईसीडी क्षेत्र के 50 करोड़ लोग (और लगभग सभी औद्योगिक इकाइयाँ) उदारीकृत बाजारों के दायरे में आ जाएंगे। (आईईए : 2001)।

विद्युत क्षेत्र के संस्थागत ढांचे में परिवर्तनों के पक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं। भूमंडलीकरण के संदर्भ के हवाले से कहा जा रहा है कि बिजली उत्पादन पर राज्य का एकाधिकार नई अभियांत्रिकी एवं उद्यमशील नीतियों के रास्ते में रोड़े अटकाता है। यह भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर सरकारों के पास बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए पर्याप्त धन नहीं है। जहां सार्वजनिक स्वामित्व ही एकमात्र विकल्प नहीं है, वहां दरों के तय करने और दूरगामी नीतियों के निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप को बिजली बाजार को विकृत करने का दोषी ठहराया जा रहा है। (विश्व बैंक : 1999)।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) का दावा है कि बेहतर आर्थिक कार्य–निष्पादन, कम दाम और उपभोक्ताओं को कई विकल्पों की उपलब्धि के जरिए मुक्त–बाजार पर आधारित बिजली सुधार निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। (आईईए : 1999ए और 1999बी)। बिजली क्षेत्र में सुधार को विकास एवं अन्य कार्यों के लिए वित्तीय सहायता की बुनियादी शर्त बनाने की वाशिंगटन आमराय का अनुपालन करने वाली बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भी यही राय है।। (टैल्लम : 2000)।

संक्षेप में, शक्तिशाली निजी स्वार्थ

और विचारधारात्मक मान्यताएं विद्युत सुधार को हवा दे रही हैं। निजीकरण और विनियंत्रण के पैरोकारों के तर्क हैं: 1. संसाधनों के प्रबंधन और विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में बिजली क्षेत्र ज्यादा कार्यकुशल है; 2. ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा और कम से कम सरकारी हस्तक्षेप के चलते आर्थिक दक्षता बढ़ेगी, परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कम दाम पर बिजली मिल सकेगी; 3. बाजारोन्मुख नीतियों के चलते उपभोक्ताओं के पास विकल्पों की सुलभता के माध्यम से विद्युत प्रणाली पर जनतांत्रिक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है; 4. विद्युत क्षेत्र के उदारीकरण के तहत पुरातन और गंदी तकनीकों को हटाने से पर्यावरण बेहतर होगा।

इस पुस्तिका के अगले चरण में नवउदारवादी मिथकों की असलियत बताने का प्रयास किया गया है।

विद्युत उदारीकरण के मिथकों की असलियत

मिथक–1

उदारीकरण के बाद विद्युत क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ जाएगी:

मुक्त बाजारवादियों का कहना है कि कार्यकुशलता और मुनाफ़ाखोरी में सामंजस्य बैठाया जा सकता है। जाहिर है कि विद्युत बाजार में दाम बढ़ाकर मुनाफे में आसानी से इजाफ़ा किया जा सकता है। लेकिन निजी स्वामित्व और प्रबंधन बेहतर कार्यकुशलता की गारंटी नहीं है।

बिजली क्षेत्र के एक अंतर्राष्ट्रीय तथ्यात्मक अध्ययन में पाया गया कि निजी और सार्वजनिक स्वामित्व के चलते कार्यकुशलता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसमें 14 देशों की बिजली कंपनियों के उत्पादन मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। बिजली के उत्पादन के मामले में एक जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली निजी और सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता एक जैसी पाई गई। संचरण और वितरण के मामलों में दोनों में कोई तकनीकी फर्क नहीं है। अध्ययन का निष्कर्ष

है कि "बिजली आपूर्ति उद्योग में सरकारी उपक्रमों में सुधार और बेहतर सरकारी प्रबंधन ही सर्वाधिक लाभकारी है" (पोल्लिट : 1995)।

जहां तक निजीकरण और विनियंत्रण से विद्युत कंपनियों की सेवाओं की गुणवत्ता में कथित सुधार का सवाल है, जिन देशों, शहरों और राज्यों ने बिजली का उदारीकरण कर लिया है वहां बिजली गुल रहने के लंबे दौर उसकी हकीकत बयान करते हैं। ऑकलैंड, कैलीफोर्निया और ब्राजील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मुनाफे की लालसा उपभोक्ताओं के अधिकार को गौड़ बना देती है। अर्जेंटीना में निजीकरण शुरू होने के नौ साल बाद, 1999 में लगातार 10 दिन तक बिजली गुल रही, वह भी भीषण गर्मी में। 500,000 लोग ओरे में बिना पानी और वातानुकूलन के गर्मी की विभीषिका झेलते रहे। निजीकरण के 1000 पृष्ठों वाले अनुबंध–पत्र में उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में महज दो पृष्ठ लिखा गया है।

बिजली गुल होने का कारण एक विद्युत उपकेंद्र में आग लग जाना था। विद्युत कंपनी ने निजीकरण के बाद श्रम शक्ति और रखरखाव के मद में भारी कटौती कर दिया जिसके चलते संचरण को दुबारा जल्दी शुरू करने के लिए न तो कंपनी के पास तकनीकी क्षमता थी और न ही प्रबंध–कौशल (सिफारेल्ली : 2000)। बाजारोन्मुख विमर्श के बावजूद निजी कंपनियां कभी भी जहां भी और जब भी संभव हो, सार्वजनिक क्षेत्र की मदद लेने से नहीं हिचकतीं। 1999 में जब समुद्री तूफान ने भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में तबाही मचा दी थी, अमरीकी कंपनी एईएस ने सरकार से यह मांग की कि उसे 600 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति अदा की जाय अथवा बिजली की दरों में तीन गुणा बढ़ोत्तरी की अनुमति दी जाए। कंपनी का कहना है कि उसकी यह मांग तूफान से उन संपत्तियों की क्षति के लिए है जिनका बीमा नहीं हुआ था (घोष : 1999)।

बाक्स–1
न्यूजीलैंड : निजीकरण का अंधियारा पक्ष

बाजारोन्मुख विद्युत सुधारों की नाकामी का ज्वलंत उदाहरण है न्यूजीलैंड। यहां विद्युत क्षेत्र का आमूल 'सुधार' हुआ और इस देश के मुख्य शहरों के निवासी रोशनी के लिए तरस गए। मुख्य फीड में गड़बड़ी हो जाने से फरवरी से मई, 1998 तक

देश का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र ऑकलैंड घुप्प अंधेरे में डूबा रहा। व्यापारिक गतिविधियों के लिए जेनरेटरों का इस्तेमाल करना पड़ा या व्यापार ही कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया और हजारों मजदूरों को घर बैठा दिया गया।

कुछ उपभोक्ताओं के मुआवजे और मरम्मत के कार्यों के लिए स्थानीय निजी कंपनी, मर्करी को 12.8 करोड़ डॉलर (न्यूजीलैंड) खर्च करना पड़ा। जुलाई 1998 में मर्करी ने घोषणा कर दी कि वह शेयरधारकों को लाभांश देने में असमर्थ है क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही थी। 1997 में 8.21 करोड़ डॉलर के मुनाफे वाली कंपनी मार्च, 1998 तक आते–आते 2.53 करोड़ डॉलर के घाटे की स्थिति में पहुंच गई। एक सरकारी जांच में पाया गया कि कंपनी के अधिकारी और इंजीनियरों को कई साल से बिजली की आपूर्ति में गड़बड़ी की संभावनाओं की जानकारी थी लेकिन कंपनी देश के विद्युत क्षेत्र पर कब्जा जमाने के उन्माद में इस कदर खो गई कि उसे आपूर्ति की वैकल्पिक योजनाओं की सुध ही नहीं रही (रोजनबर्ग और केल्सी : 1999)।

बिजली गुल होने की यह मिसाल तो 1984 में शुरू हुए ढांचागत समायोजन के कुल दुष्परिणामों का एक छोटा सा नमूना भर है। योजनाबद्ध ढंग से चली 'सुधारों' की इस प्रक्रिया के तहत देश की सभी फायदेमंद सार्वजनिक सेवाएं निजी क्षेत्र के नियंत्रण में आ गई हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में 'सुधारों' की प्रक्रिया और दक्षिण के देशों पर थोपी गई इसी तरह की प्रक्रिया में एक खास फर्क है। यहां ऐसा विश्व बैंक, आईएमएफ या क्षेत्रीय बैंकों की शर्तों के दबाव में नहीं हुआ, बल्कि यह सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के वैचारिक स्तर में नाटकीय बदलाव का नतीजा है। 1980 के दशक में न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी अपना पारंपरिक लोकतांत्रिक–समाजवादी वैचारिक समझ त्यागकर थैचरवादी उदारवाद के वैचारिक पथ पर चल पड़ी। 1990 के बाद मुक्त–बाजार का गान गाने वाली किन्तु हकीकत में, पारंपरिक रूप से हस्तक्षेपवादी, दक्षिणपंथी सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया।

बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया 1986 में न्यूजीलैंड के बिजली विभाग की इलैक्ट्रीकार्प उत्पादन, संचरण और फुटकर उपभोक्ता सेवा की तीन अलग–अलग इकाइयों में बंटे सरकारी उपक्रम में तब्दीली के साथ शुरू हुई। सभी स्तरों पर बाजार प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को लागू किया गया। 1993 में सरकार ने तमाम स्थानीय बिजली कंपनियों का गठन करके उपभोक्ताओं को शेयरधारक बनाने की पेशकश की। इसके बाद तो समय का पता ही नहीं चला कि कब सारे देश के बिजली–क्षेत्र पर मुट्ठीभर विदेशी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया।

बिजली के निजीकरण का सबसे अधिक प्रतिरोध स्थानीय समुदायों ने किया। स्थानीय विधायकों पर सार्वजनिक सेवाओं को सरकारी क्षेत्र में वापस लेने के लिए नागरिक संगठनों का जबरदस्त दबाव पड़ रहा है और नगरपालिकाओं में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहसें चल रही हैं। न्यूजीलैंड के बाजारोन्मुख कानूनों के चलते इन संगठनों के मकसद की कामयाबी में मुश्किलें हैं लेकिन कई संगठन बिजली के आधारभूत ढांचे पर स्थानीय सरकारों का नियंत्रण स्थापित कराने में कामयाब रहे हैं।

बॉक्स–2

ब्राजील : बिजली कंपनियों के बजाय सेंट पीटर के मत्थे दोष मढ़ना अधिक आसान

ब्राजील की संभावित जल–विद्युत क्षमता की तुलना सउदी अरब की तेल क्षमता से की जाती है। इसकी वेगवती नदियां दुनिया की सबसे सस्ती बिजली पैदा करती हैं। नए बने जल–विद्युत संयंत्रों की बिजली का औसत दाम 16 डॉलर प्रति मेगावाट प्रतिघंटा है। निर्माण व्यय का भुगतान कर चुके लोगों के लिए यह आधा हो जाता है। 1950 से ब्राजील सरकार ने जल विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त निवेश शुरू किया और 1990 का दशक खत्म होते–होते ये संयंत्र देश की कुल बिजली की जरूरत के 91 प्रतिशत की आपूर्ति करने लगे। ब्राजील जल–विद्युत उद्योग के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन गया बांध नियोजन से लेकर दुनियाभर में बिजली परियोजनाओं के लिए प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने के सभी क्षेत्रों में इसके बावजूद मई से अगस्त 2001 के दौरान सारे देश को बिजली संकट के बुरे दौर से गुजरना पड़ा। भारी आर्थिक घाटे के चलते तीन महीने तक बिजली गुल होना और अनिवार्य नियंत्रित वितरण के उपायों का इस्तेमाल करना आम बात हो गयी थी। (कोस्टा : 2001)।

पिछले चार सालों से ब्राजील में वर्षा का नयूनतम स्तर बरकरार है, और इसलिए राष्ट्रपति ई.एच.कोर्डोसो ने बिजली संकट की जिम्मेदारी 'सेंट पीटर की मर्जी' के मत्थे मढ़ दिया। दरअसल ब्राजील के बिजली संकट की जड़ है 1990 के दशक से शुरू हुई ब्राजील की विद्युत प्रणाली के 'नियंत्रित विघटन' की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया की शुरूआत 1993 में वितरण कंपनियों के निजीकरण से हुई। निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान, नए मॉडल को कार्यरूप देने के लिए, अफरातफरी में, एक नियंत्रण निकाय के रूप में राष्ट्रीय विद्युत एजेंसी (एएनईईएल) का गठन किया गया। नतीजतन इंगलैंड की ब्राजील की एकीकृत बिजली प्रणाली की समग्रता भंग हो गई और वितरण के विनियंत्रण से शुरू होकर धीरे–धीरे उत्पादन और संचरण निजीकरण की चपेट में आते गए।

इन सुधारों का एक अहम पहलू ब्राजील के विद्युत ढांचे को इस तरह संशोधित करना था जिससे कि वह आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भर हो जाए। नई उदारीकृत योजना के तहत उत्पादन क्षमता में 25 प्रतिशत योगदान प्राकृतिक गैस का होगा। लेकिन जैसाकि हाल के बिजली संकट के दौरान देखा गया, इतना ही शेयर पूरी विद्युत प्रणाली पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त है।

विद्युत संकट के दौरान देश की संघीय सरकार पर एनरॉन जैसी अमरीकी और यूरोपीय बहुराष्ट्रीय प्राकृतिक गैस कंपनियों के भारी दबाव की बात स्पष्ट रूप से सामने आई। प्राकृतिक गैस उत्पादक संघ अमरीकी मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीएए) के विद्युत विस्तार अध्याय का प्रमुख खिलाड़ी है जिसे अमरीकी सरकार और कॉरपोरेट लॉबीका समर्थन हासिल है। ब्राजील में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बोलीविया की प्राकृतिक गैस उत्पादन पर निर्भर है। बोलीविया के गैस उद्योग पर एनरॉन, शेल, ब्रिटिश गैस एवं अन्य विद्युत कंपनियों का नियंत्रण है। लगता है यही कंपनियां पेरू

के गैस भंडारों पर भी काबिज हो जाएंगी। गौरतलब है कि भविष्य में विशाल अर्धभूमंडलीय नेटवर्क के प्रथम चरण के रूप में पेरू में प्राकृतिक गैस के उत्पादन को ब्राजील की विद्युत प्रणाली से जोड़ा जा सकता है।

इस संकट की चेतावनी विशेषज्ञों द्वारा जारी तथ्यपरक रिपोर्टों से काफी पहले ही मिल गई थी। शोधजनित तथ्यों पर आधारित विशेषज्ञों की इन रिपोर्टों में संकलित आपूर्ति भंडार के संभावित सिमटाव के खतरों की विस्तृत जानकारी दी गई थी। इन चेतावनियों को नजरअंदाज करके सरकार मिथ्या–विश्वास के सहारे बैठी रही और दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस के निजी संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया धड़ल्ले से चलती रही। यदि ब्राजील के पास एक सुव्यवस्थित बिजली बचत कार्यक्रम नहीं होता तो यह संकट और भी भीषण हो सकता था। गौरतलब है कि 1985 में कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से इस कार्यक्रम के तहत 5,000 मेगावाट/घंटा से अधिक बिजली की बचत हुई थी (हांटी : 2002)।

वित्तीय संसाधनों की सहज उपलब्धता के बावजूद संकट से पहले सरकार को नए संयंत्रों और संचार सुविधाओं में निवेश नहीं करने दिया गया। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के साथ हुए एक समझौते में उत्पादन और संचार नियंत्रित करने वाली सरकारी कंपनियों द्वारा नए निवेश की मनाही की शर्त रखी गई थी। समझौते की शर्त के तहत ऐसे निवेश को सार्वजनिक घाटा माना जाएगा और इस तरह ब्राजील आईएमएफ द्वारा निर्धारित सार्वजनिक बजट के लक्ष्य को हासिल करने से चूक सकता है।

संक्षेप में कहें तो ब्राजील के बिजली संकट ने स्पष्ट कर दिया है कि विद्युत क्षेत्र का उदारीकरण तकनीकी और आर्थिक दोनों ही आधारों पर अनुचित था। यह तेज बाजारवादी विचारधारा और विदेशी कंपनियों के व्यापारिक हितों से प्रेरित था। ब्राजील पर दबाव डाला गया कि वह इस क्षेत्र में लाभ की स्थिति छोड़ दे ! यानि, सस्ते घरेलू संसाधनों पर आधारित जल–विद्युत संयंत्र स्थापित करे। 1950 से विद्युत क्षेत्र में रणनीतिक योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। अब यह जिम्मेदारी विदेशी कंपनियों को सौंप दी गई। इस काम को सम्पन्न करने के लिए बिजली संकट को न केवल काबिले–बर्दाश्त बताया गया बल्कि वांछनीय भी। किसी कृत्रिम संकट की संभावना ही ऐसे कुतर्कों को उचित ठहरा सकती है !

बॉक्स–3
अमरीका : कैलीफोर्निया के नाकाम विनियंजण से सीख

भूमंडलीय आर्थिक उदारीकरण के मसीहा, अमरीकी महाप्रभु की ही धरती पर निजीकरण को बढ़ावा देने और बिजली की दरों में कमी के माध्यम से विनिवेश द्वारा लोगों की जिंदगी सुधारने के दावे की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सारे अमरीका में इस बात के काफी तथ्यात्मक सबूत मिले हैं कि विनियंत्रित विद्युत बाजार में उपभोक्ताओं से निम्नस्तरीय सेवा के लिए काफी ऊंची कीमतें वसूली जा रही हैं

और निजी कंपनियां बेहिसाब मुनाफा कमा रही हैं। कैलीफोर्निया में विनियंत्रण के बाद से विद्युत संयंत्रों में बिना पूर्व सूचना के बिजली गुल होने की दर 461 प्रतिशत हो गई है। इसमें 2000 और 2001 के लंबी अवधि के बिजली गुल के भयावह अनुभव भी शामिल हैं (सोलोकम : 2001)।

कैलीफोर्निया संकट से पता चला कि कैसे विद्युत कंपनियों के एक संगठित गिरोह ने उपभोक्ताओं, व्यापारियों और कर दाताओं से खरबों डॉलर लूट लिया। कैलीफोर्निया संकट की गणना अमरीकी इतिहास के घोर अनर्थों में होती है। 1996 के बाद बिजली की दरों के निर्धारण में राज्य का नियंत्रण खत्म हो जाने से विद्युत कंपनियों को आपूर्ति में हेरा–फेरी, बनावटी कमी और विद्युत की जमाखोरी के जरिए अकूत मुनाफा कमाने का सुनहरा अवसर मिल गया। नतीजतन 1996 के बाद से कैलीफोर्निया के निवासियों को, सार्वजनिक सुविधा की कंपनियों की फीस, लंबी अवधि का विद्युत अनुबंध एवं अन्य खर्चों को मिलाकर बिजली पर लगभग 71 खरब डालर खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि हर स्त्री–पुरूष या बच्चे पर 2100 डॉलर बिजली के भुगतान का बोझ पड़ता है (एफटीसीआर : 2001)।

कैलीफोर्निया में बिजली संयंत्रों के मालिकों ने आपूर्ति घटाने और थोक भाव बढ़ाने के मकसद से जानबूझ कर संयंत्रों को बंद करने का नाटक किया। बिजली व्यवस्था के संचालन की देखरेख करने वाली सरकारी एजेंसी, कैलीफोर्निया इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर ने पाया कि बिजली उत्पादकों ने राज्य की सार्वजनिक सेवा विभाग से 2000 में 24.7 करोड़ डॉलर और 2001 में 31.5 करोड़ डॉलर अधिक की वसूली की थी (सोलोकम : 2001)।

बिजली संयंत्रों और संचार के एकाधिकार पूंजीवादी स्वामित्व वाली कंपनियों के शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, 20वीं शताब्दी की शुरूआत से ही अमरीका में सार्वजनिक सेवाओं के नियंत्रण की नीति जारी रही। ज्यादातर राज्यों में अभी भी जारी नियंत्रण की पुरानी व्यवस्था के तहत सेवाओं के लिए मुनाफे की गारंटी तो है लेकिन साथ ही उपभोक्ताओं के लिऐ स्थिर दर और आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान हैं। 1990 के दशक में इस व्यवस्था में परिवर्तन तब शुरू हुआ जब बड़े औद्योगिक घराने अपने सेवा क्षेत्र से बाहर के स्रोतों से सस्ती बिजली खरीदने का रास्ता सुलभ बनाने के उद्देश्य से विनियंत्रण का राग अलापने लगे।

विनियंत्रण के बाद आपूर्ति और मांग के सिद्धांत पर बिजली के दामों में उतार–चढ़ाव आने लगा और बिजली गुल होने की घटनाएं आम हो गईं। सार्वजनिक क्षेत्र को अपने संयंत्रों को फुटकर दर पर निजी हाथों में बेचने को बाध्य किया गया। संयंत्रों के नए मालिक थोक बाजार से बिजली खरीदकर अपने ग्राहकों को बेचते थे। विधि निर्माताओं की सोच यह थी कि तमाम नए फुटकर विक्रेता स्थापित सार्वजनिक सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करेंगे और 'मुक्त बाजार' की इस प्रतियोगिता से दामों को नीचे रखा जा सकेगा। बिजली संयंत्रों के नए मालिकों को हर प्रकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार कैलीफोर्निया की राज्य सरकार का न तो बिजली व्यापारियों द्वारा वसूले जाने वाले नए थोकमूल्य पर कोई नियंत्रण रहा और न ही बिजली उत्पादन की मात्रा पर। इस स्थिति में

कुछ ही कंपनियों ने नये विनियंत्रित बाजार से संयंत्रों को खरीदा। आपूर्ति के नियंत्रण पर इन्हीं कंपनियों का वर्चस्व कायम हो गया और ये मनचाहे दाम वसूलने लगीं।

नया बिजली बाजार विद्युत संयंत्रों के मालिकों और बिजली के व्यापारियों के लिए अकूत मुनाफा कमाने का कामधेनु साबित हुआ। कैलीफोर्निया में बिजली की थोक दरों को नियंत्रित करने का अधिकार केवल अमरीका के संघीय नियंत्रण आयोग (फेडरल रेगुलेटरी कमीशन) के ही पास है, लेकिन बढ़ते संकट के बावजूद संघीय नियंत्रण आयोग ने दखल नहीं दिया और संकट गहराता गया। एनरॉन कैलीफोर्निया बिजली बाजार का प्रमुख खिलाड़ी था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति जार्ज बुश की चुनाव राशि में इस कंपनी का प्रमुख योगदान रहा है।

कैलीफोर्निया संकट से सीख लेकर विनियंत्रण की कगार पर खड़े कई अन्य राज्यों ने इसे फिलहाल टाल दिया है। अर्कन्सास ने विनियंत्रण के कार्यान्वयन को एक साल के लिए टाल दिया है। नेवादा ने इसे तुरंत ही रोक दिया और न्यू मैक्सिको ने इसे पांच साल के लिए टाल दिया है। ओक्लाहोमा के विधि निर्माताओं ने इसके कार्यान्वयन को और दो साल के लिए आगे बढ़ा दिया। कई राज्य मान रहे हैं कि नए बिजली संयंत्रों की स्थापना से कैलीफोर्निया जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। सारे देश में नीति निर्माताओं पर कड़े विद्युत नियंत्रण, संरक्षण के उपायों और विद्युत के वैकल्पिक स्रोतों के लिए दबाव पड़ रहा है। जब बिजली संकट से बाकी कैलीफोर्निया में त्राहि मची थी तब लॉस एंजेल्स एवं कैलीफोर्निया के 30 अन्य शहर इस संकट से अप्रभावित रहे, क्योंकि इन शहरों में बिजली क्षेत्र नगरपालिका के नियंत्रण में थी। कैलीफोर्निया संकट से सीख लेकर देशभर में बिजली पर नगरपालिका के नियंत्रण स्थापित करने की मुहिम सी चल पड़ी। सैन्फ्रांसिस्को, न्यू आर्लियंस, पोर्टलैंड तथा कई अन्य प्रमुख शहरों में तो स्थानीय जनमत संग्रह के माध्यम से बिजली के उत्पादन और वितरण पर स्थानीय सार्वजनिक नियंत्रण का प्रावधान कर दिया गया। कैलीफोर्निया में सामाजिक सरोकार वाले व्यक्तियों, पर्यावरणविदों, उपभोक्ता समूहों, यूनियनों, सामुदायिक समूहों और व्यापारिक संघों का एक व्यापक गठबंधन स्वच्छ, सुलभ और सार्वजनिक विद्युत के लिए 'पॉवर टू पीपुल' अभियान चला रहा है।

मिथक–2

उदारीकरण के बाद बिजली सस्ती हो जाएगी

जनता के बीच उदारीकरण को उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। दुनियाभर के उदारीकरण के अनुभव इसके विपरीत हैं। विनियंत्रित, निजी बिजली बाजार में उत्पादकों और वितरकों द्वारा दाम के मनमाने निर्धारण पर कोई रोक नहीं है। नियंत्रक बिजली गुल होने की स्थिति से बचने के लिए बिजली का एक न्यूनतम आरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं।

बाजारवादियों का तर्क है कि बाजार खुद दाम और आपूर्ति की कमी की समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं लेकिन अधिकतम मुनाफा कमाने के मकसद से निजी उत्पादक उत्पादन घटाकर बिजली की कमी की स्थिति पैदा कर सकते हैं और दामों में इजाफा।

कैलीफोर्निया में,1996 में जब विनियंत्रण लागू किया गया तो उदारीकरण के पैरोकारों ने बिजली के दाम में कम से कम 20 प्रतिशत कमी का दावा किया था। लेकिन 2000 के संकट के बाद जब दाम आसमान छूने लगे तो वही लोग यह कहने लगे कि प्रतिस्पर्धा के प्रोत्साहन के लिए उपभोक्ता दर में वृद्धि आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों के उदाहरण इस मान्यता को झुठलाने वाले हैं। कैलीफोर्निया के नगरपालिका नियंत्रित बिजली व्यवस्था वाले 30 शहरों के उपभोक्ताओं को वही बिजली काफी कम कीमत पर मिलती है (हंटर और स्लोकुम : 2001)।

कैलीफोर्निया बिजली संकट के दौरान एनरॉन एवं अन्य विद्युत व्यापारियों ने संदिग्ध तकनीकों से बिजली के दामों में मनमानी वृद्धि की, जैसा कि एनरॉन के वकीलों का कहना है, "हो सकता है संकट को गंभीर बनाने में उन्होनें योगदान दिया हो"। मई 2002 में अमरीका के संघीय नियंत्रण आयोग द्वारा जारी कंपनी के दस्तावेज खुद सारी कहानी बयान करते हैं। कैलीफोर्निया सार्वजनिक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अनुसार, "ये दस्तावेज साबित करते हैं कि ये कंपनियां धूर्तता से बाजार में हेरा–फेरी कर सकती हैं। ज्ञापनों में वर्णित एक रणनीति के तहत एनरॉन सरकारी संयंत्र से 250 डॉलर प्रति मेगावाट घंटे की दर से बिजली खरीद कर अन्य राज्यों में उसे पांच गुना दाम पर बेचेगी (ओप्पेल और गर्थ : 2002)।

यूरोप में उदारीकरण से बिजली के दामों में जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन प्रमुखतः व्यापारिक क्षेत्र के लिए। कहा जा रहा है, "उदारीकरण से समग्रता में बिजली की दरें नहीं घटीं, बल्कि यह 'जमा–खर्च बराबर' का खेल है। घरेलू इस्तेमाल के उपभोक्ताओं को थोड़ा ज्यादा दाम देना पड़ता है तो व्यापारिक उपभोक्ताओं को थोड़ा कम" (हाल : 2001 :8)। मार्च 2002 में वार्सीलोना सम्मेलन में अपने देशोंकी राय जाने बिना, यूरोपीय नेताओं ने यूरोपीय संघ के मौजूदा कानूनों में 2004 तक गैस और बिजली क्षेत्र में 60 प्रतिशत उदारीकरण सुनिश्चित करने वाले बदलाव को सहमति दे दी।

मिथक–3

बिजली का उदारीकरण पर्यावरण के लिए लाभप्रद है

दूरगामी दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो उदारीकरण बिजली व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा बिजली बेचने का प्रलोभन देता है। निजी कंपनियों का मुख्य सरोकार पर्यावरण की ज्यादा परवाह किए बिना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। निजीकरण और विनियंत्रण सस्ते किंतु प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल का प्रलोभन प्रदान करते हैं। यह ईंधन संयंत्र में ज्यादा समय तक चलता है किंतु प्रदूषण भी ज्यादा फैलाता है। मुक्त बाजार के कानूनों के ढांचे में नए मालिक नए उपकरण लगाने की बजाय पुराने से ही काम चलाते हैं। नए संयंत्र भी लगेंगे, क्योंकि उदारीकरण से मांग बढ़ेगी, खासकर औद्योगिक उपभोक्ताओं में। उदारीकरण का संभावित दूरगामी परिणाम होगा–विकिरण में वृद्धि और वायु के प्रदूषण स्तर में गिरावट। वैसे भी चूंकि विनियंत्रित बिजली बाजार नैसर्गिक रूप से अस्थिर और विषम होता है, और बाजार पर कुछ वितरकों का नियंत्रण अधिक होता है, इसलिए एक बड़ा आरक्षित भंडार आवश्यक है। इससे उत्पादक पर्यावरण नियंत्रण में ढील देंगे तथा संयंत्र एवं संचार लाइनें स्थापित करेंगे।

दुनियाभर के अनुभवों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बिना समुचित सरकारी हस्तक्षेप के विद्युत क्षेत्र के उदारीकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील कई क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आएगी (बॉक्स–7), और ग्रीन हाउस गैस के विकिरण से भूमंडलीय वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मिथक–4

सरकारें अपना रास्ता खुद चुन सकती हैं : निजीकरण और विनियंत्रण थोपा नहीं जाएगा

कर्जदाता के दबाव के तहत और विचारधारा के रूप में निजीकरण और विनियंत्रण सरकारों पर थोपा जा रहा है। सरकारों को अनिवार्यतः विश्व बैंक, आईएमएफ या क्षेत्रीय विकास बैंकों को विद्युत क्षेत्र के उदारीकरण की शर्त के साथ एक मानक 'आशय पत्र' देना पड़ता है।

वाशिंगटन आम सहमति में तो उदारीकरण की राजनीति को

अनुशंसा बहुत ही सहज ढंग से की गई है। 1997 की विश्व विकास रिपोर्ट, 'बदलते विश्व में राज्य' पर सरसरी निगाह डालने से लगता है कि विश्व बैंक ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण की नीति छोड़कर एक मजबूत राज्य की हिमायत शुरू कर दी है। लेकिन इसके तथा इसी तरह के अन्य अधिकाधिक दस्तावेजों के सूक्ष्म विश्लेषण से पता लगता है हकीकत जस–की–तस बनी हुई है। उपरोक्त रिपोर्ट में विश्व बैंक का मत है कि निजीकरण और विनियंत्रण पर बहस नहीं होनी चाहिए बल्कि 'आमराय बनाने' के जरिए लोगों को 'सुधारों के फायदों' के बारे में समझाना चाहिए। सितंबर 1999 में विश्व बैंक और आईएमएफ ने बहुचर्चित, कुख्यात विस्तृत ढांचागत समायोजन सुविधा (एन्हान्स्ट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फसिलिटी – ईएसएएफ) की जगह कर्ज रियायत के 'नए' ढांचे के तौर पर तथाकथित गरीबी उन्मूलन एवं विकास सुविधा (पावर्टी रिडक्शन संड ग्रेथ फेसिलिटी–पीआरजीएफ) योजना शुरू किया। 2001 में ब्राजील का बिजली संकट सार्वजनिक क्षेत्र के विरूद्ध विश्व बैंक और आईएमएफ के अटल दुराग्रह की पुष्टि करता है (बॉक्स–2) यदि ये वित्तीय संस्थान सार्वजनिक निवेश पर कठोर प्रतिबंध न लगाते तो संकट से बचा जा सकता था।

भूमंडलीय उदारीकरण का नया प्रमुख एजेंट डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) है। जब बिजली "सरकारी अधिकार से संचालित सेवा" नहीं रही तो डब्लूटीओ के सरोकार का विषय बन गई और विदेशी कंपनियों को बिना किसी प्रतिबंध के इसके व्यापार की छूट मिल गई। (गैंडर स्टिचेले : 2002)। यूरोपीय आयोग द्वारा तैयार कुछ गोपनीय दस्तावेजों के लीक अंशों से डब्लूटीओ के सदस्य देशों – भारत, अमरीका, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, उरूग्वे आदि – को पेश की गई यूरोपीय संघ की मांगों का पता चलता है। लीक हुए दस्तावेजों से विद्युत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खोल देने तथा इसके उत्पादन, संचरण और वितरण को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त करने के लिए बढ़ते दबाव का पता चलता है। (एचटीटीपी : डब्लूडब्लूडब्लू.ऑर्ग)।

भारी कर्जदार गरीब देशों (हेविली इंडेन्टेड पुअर कंट्रीज–एचआईपीसी) की पहल में शामिल करने के एवज में दक्षिण के गरीब देशों पर निजीकरण की शर्त थोपी जा रही है। कर्ज से रियायत पाने के लिए

इन देशों को विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा निर्धारित ढांचागत समायोजन के क्रियान्वयन में प्रगति का लेखा–जोखा देना पड़ता है। उनसे 'गरीबी उन्मूलन रणनीतिक प्रपत्र' लिखवाया जाता है जो वस्तुतः निजीकरण के प्रति प्रतिबद्धता के वायदों का पुलिंदा होता है। (बेलिस : 2002)।

मिथक–5

बिजली का उदारीकरण लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है

उदारीकरण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति पर बड़ी कंपनियों का नियंत्रण कायम करने का माध्यम है। निजी कंपनियां सार्वजनिक एकाधिकार को बेदखल करके निजी एकाधिकार कायम करती हैं। इसका दूरगामी परिणाम यह होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भी ताकतवर हो जाएंगी और बिजली आपूर्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भूमंडलीय हितों की रखैल बन जाएगी। चार्ट–1 में अंतर्राष्ट्रीय बिजली बाजार पर चंद अमरीकी और यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कायम होता आधिपत्य दर्शाया गया है। चार्ट में दिखाई गई पहली दो कंपनियों ने आपस में दुनिया का बंटवारा कर लिया है। लैटिन अमरीका के बिजली बाजार में प्रमुख निवेशक एंडेसा है (बॉक्स–4) तो पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और एशिया के उदारीकृत बाजारों पर एईएस का आधिपत्य है।

1990–91 के दौरान 10 प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दक्षिणी देशों की ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश (खरब अमरीकी डॉलर)

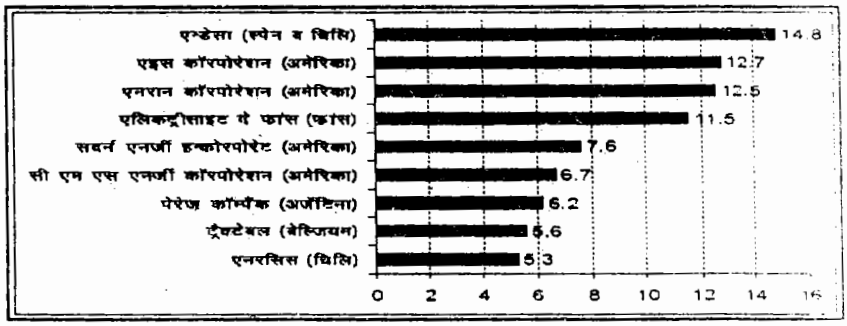

नोटः इस चार्ट में उन्हीं परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिनमें प्रायोजक का शेयर कम से कम 15 प्रतिशत है। परियोजना का आंकड़ा कुल निवेश का है, केवल निजी निवेश का नहीं।
स्रोतः इजाग्विरे (2000) में प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर व्याख्या

बॉक्स–4

कोलंबिया : दूसरा स्पेनी हमला

कोलंबिया में निजीकरण का इतिहास भ्रष्टाचार के मामलों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मनमाने मुनाफे की कहानियों का पुलिंदा है। तमाम सार्वजनिक संपत्तियां स्पेनी कंपनियों को सौंपी जा रही हैं। ये कंपनियां वित्तीय और विद्युत क्षेत्र के काफी हिस्से पर पहले से ही काबिज हैं। इन व्यापारिक दखलंदाज़ियों को 'दूसरे स्पेनी उपनिवेशवाद' की संज्ञा दी जा सकती है।

कोलंबिया प्रचुर तेल भंडार वाला देश है, फिर भी उसे 1970 और 1980 के दशकों के संकट के दौरान 5 से 35 डॉलर प्रति बैरल के भाव से तेल आयातित करना पड़ा। इसी समय बहुआयामी विकास बैंकों ने आसान शर्तों पर अपार जल संसाधनों से संपन्न कोलंबिया जैसे देशों में विशाल जल–विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज को तरजीह देने की नीति पर चलना शुरू किया। आंडेअन क्षेत्र में बड़े–बड़े बांध और जलाशय के निर्माण के चलते कोलंबिया पर विदेशी कर्ज का भार बढ़ता गया। 1980 के दशक के मध्य तक कोलंबिया एक तेल निर्यातक देश बन गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में गिरावट आई। तेल निर्यात का काफी हिस्सा कर्ज अदायगी में चला जाता है।

1991 में नए राजनैतिक संविधान के पारित होने के बाद कोलंबिया में सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। दक्षता के नाम पर, बाजार–प्रतिस्पर्धा के लिए कानूनों में फेर–बदल की जरूरत थी। व्यवहार में इसका मतलब है कि एक संवेदनशील क्षेत्र की संपत्ति को निजी कंपनियों के हाथों सौंप देना। 1994 में निजीकरण को सहज बनाने के लिए, भ्रष्ट नौकरशाही और अत्यधिक उत्पादन–मूल्य (कुछ मामलों में 300 प्रतिशत) से निजात पाने के नाम पर, विद्युत अधिनियम पारित हुआ। कुछ हद तक ये बातें सही थीं, लेकिन कुछ ही कंपनियों के मामले में।

निजीकरण की प्रक्रिया में कई राष्ट्रीय स्तर के घोटाले हुए। एल गुआविओ जल–विद्युत कांड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसे कोलंबिया में 'शताब्दी का सबसे बड़ा व्यापारिक घोटाला' के रूप में जाना जाता है। एल गुआविओ का निर्माण 1980 के दशक में विश्व बैंक के 35.9 करोड़ डॉलर के कर्ज से शुरू हुआ। भ्रष्टाचार, अधिक दाम और लचर प्रशासन की कहानियों के बीच 240 करोड़ डॉलर की लागत से परियोजना का पहला चरण 1993 में पूरा हुआ। दूसरे चरण के लिए और 14 करोड़ डॉलर चाहिए था। तीन महीने बाद सरकारी बिजली कंपनी आईएसए को बाध्य किया गया कि वह एल गुआविओ में अपना 40 प्रतिशत शेयर बोगोटा के जिला प्रशासन को बेच दे। इसके लिए उसे आईएडीबी के कर्ज से 24 करोड़ डॉलर भुगतान किया गया। अंततः कुल 240 करोड़ डॉलर के निवेश के बाद मूल निवेश के आधार पर आईएसए का शेयर 30 प्रतिशत ही रह गया। तीन महीने बाद बिना किसी लाभ के कंपनी को 72 करोड़ डॉलर का शेयर छोड़ देने को बाध्य किया गया।

एल गुआविओ के पहले चरण के उद्घाटन भाषण में कोलंबिया के राष्ट्रपति,

सीजर गवीरिआ ने कहा प्रबंधन की समस्याओं से निजात पाने के लिए पूरे विद्युत क्षेत्र को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर देना चाहिए। इस तरह 1997 में स्पेनी कंपनी एंडेसा और इससे जुड़ी चिली की कंपनी इनर्सिस ने कोलंबिया के जल विद्युत संयंत्रों– एल गुआविओ (1150 मेगावाट), गुआका (311 मेगावाट), कोलेगिओ (300 मेगावाट), लगूनेता (72 मेगावाट), साल्तो द्वितीय (70 मेगावाट) और कैनोअस (45 मेगावाट) तथा ताप विद्युत संयंत्रों जिपा द्वितीय (38 मेगावाट) एवं जिपा तृतीय, चतुर्थ और पंचम (प्रत्येक 66 मेगावाट) को खरीदने की एकमुश्त पेशकश की। एंडेसा और इनर्सिस ने इन सबके लिए कुल मिलाकर 2454 मेगावाट के चालू संयंत्रों के लिए 95.1 करोड़ डॉलर का भुगतान किया जो कि केवल एल गुआविओ के ही दाम की आधी रकम है। इस अंधाधुंध निजीकरण की दौड़ में कोलंबिआई जनता के धन से निर्मित मंहगे संयंत्रों एवं संचार साधनों को विदेशी कंपनियों के हाथों औने–पौने दामों में बेच दिया गया। जहां तक फायदों का सवाल है तो न तो बिजली के ढांचे में कोई विस्तार हुआ, न ही बिजली की सुविधाओं या आम जनजीवन के स्तर में कोई सुधार हुआ। उल्टे बिजली गुल होने की कहानियां आम बात हो गई। कहानी यहीं नहीं खत्म हो जाती। सरकार अब 14 स्थानीय सार्वजनिक सुविधाओं तथा मौजूदा हालात में आईएसए द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय संचार और वितरण ग्रिड के निजीकरण की तैयारी कर रही हैं। गौरतलब है कि ये कोलंबिया की सर्वाधिक लाभदायक कंपनियां हैं।

टीएनआई के परियोजना भागीदार सीईएनएसएटी–अगुआ विवा द्वारा तैयार किया गया।

यह प्रक्रिया दक्षिण के गरीब देशों तक ही सीमित नहीं है। यूरोप में जारी कॉरपोरेटी केंद्रीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप 2005 तक यूरोपीय संघ के बिजली बाजार पर 6–7 बिजली कंपनियों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। इन कंपनियों ने साझी कार्रवाई या फिर परिसंघ बनाकर सरकारों पर दबाव डालने, मूल्यों को नियंत्रित करने और प्रतिस्पर्धा को सीमित करने की रणनीति पहले ही तैयार कर ली है। मसलन, बेल्जियम के बिजली बाजार पर एकाधिकार वाली निजी कंपनी इलैक्ट्राबेल ने अपनी जर्मन प्रतिद्वंद्वी कंपनी आरडब्लूई से बराबर हिस्सेदारी के आधार पर जर्मन स्वामित्व वाले बीएएसएफ के संचालन का समझौता कर लिया। मुनाफा कमाने के अपने अभियान में ये कंपनियां प्रतिस्पर्धा से बचने का भरसक प्रयास करती हैं। बिजली बाजार के एकाधिकार नियंत्रण को रोकने के उद्देश्य से बिजली क्षेत्र के विघटन के सरकारी प्रयासों को धता बताते हुए, बड़ी कंपनियां संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खरीद लेने की रणनीति पर काम करती हैं। ये कंपनियां व्यापक अधिग्रहण, विलय, सट्टेबाजी एवं अन्य संदिग्ध बाजार–रणनीतियों के जरिए नियंत्रक शर्तों को धता बताने में

माहिर हैं। एनरॉन प्रकरण ने तो निजीकरण और विनियंत्रण तथा भ्रष्टाचार और प्रश्रय के रिश्तों को साफ–साफ उजागर कर दिया। (बॉक्स–5)। सन् 2000 में फिलीपींस के बिजली क्षेत्र के जिस 'सुधार' को निजीकरण के इतिहास की एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा था, वह दरअसल एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ। दो वामपंथी सांसदों ने इसका पर्दाफाश किया। संसद में राष्ट्रीय विद्युत निगम के निजीकरण का विधेयक पारित हो जाने के

बॉक्स–5
एनरॉन के मुहरे : जनता के पैसे से दुनिया भर में निजीकरण की मुहिम

सस्टेनेबल एनर्जी एंड इकॉनामी नेटवर्क (एसईईएन) द्वारा प्रकाशित एक ताजी रिपोर्ट के अनुसार दिवालिया हो चुकी एनरॉन कंपनी ने "सरकारी वित्तीय सहायता, अमरीकी अधिकारियों और उनके विदेशी सहायकों के ठोस समर्थन से खतरनाक विदेशी परियोजनाओं का ठेका ले लिया।" एनरॉन अमरीकी और विदेशी सरकारी एजेंसियों की 7 खरब डॉलर की वित्तीय सहायता से एक भूमंडलीय ताकत बन गया।

एनरॉन को मदद पहुंचाने के लिए विश्व बैंक ने दक्षिणी देशों की सरकारों को बिजली के निजीकरण के लिए बाध्य किया। बैंक ने इन सरकारों से कहा कि यदि वे इस अमरीकी कंपनी के साथ 'सहयोग' करेंगे तभी उन्हें भविष्य में कर्ज मिलेगा। अमरीका में अपनी राजनैतिक पहुंच का फायदा उठाते हुए इस कंपनी ने विनियंत्रित ऊर्जा क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। विदेशों में एनरॉन ने पाइप लाइन, संचार लाइन और विद्युत संयंत्रों पर कब्जा जमाया।

इसकी रणनीति साफ थी, "विश्व बैंक विकासशील देशों को ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के लिए कर्ज देगा या किसी भी कर्ज के लिए निजीकरण की शर्त रखेगा। ऐसे में एनरॉन बोली लगाने वाला पहला, और प्रायः सर्वाधिक सफल कॉरपोरेशन होगा, जो देश की विनियंत्रित, निजीकृत विद्युत बाजार पर काबिज हो जाएगा।" (:12)।

ओवरसीज प्राइवेट इनवेस्टमेंट कॉर्प और एक्सपोर्ट–इंपोर्ट बैंक सरीखी अमरीकी सरकारी एजेंसियों ने एनरॉन की 25 परियोजनाओं के लिए 3.7 खरब डॉलर का कर्ज दिया। विश्व बैंक ने 76 करोड़ डॉलर, इंटर–अमरीका डेवलपमेंट बैंक (आईएडीबी) ने 75.1 करोड़ डॉलर तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने 2.6 करोड़ डॉलर की राशि एनरॉन को मुहैया किया। अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों तथा सरकारों ने एनरॉन के भूमंडलीय प्रसार के लिए कुल 1.9 खरब डॉलर का अनुदान दिया। कुल मिलाकर 29 देशों में 38 परियोजनाओं के लिए एनरॉन ने सार्वजनिक स्रोतों से 7.2 खरब डॉलर का जुगाड़ किया। निजीकरण और विनियंत्रण की सबसे बड़ी पैरोकार होने के दावे के बावजूद सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से कंपनी ने कभी परहेज नहीं किया।

बाद उनके कार्यालयों में 12500 डॉलर की अवांछित राशियां पहुंचाई गईं। गौरतलब है कि इन सांसदों ने विधेयक के विरोध में मतदान किया था। इससे कयास लगाया जा सकता है कि विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सांसदों को ज्यादा धन मिला होगा। सांसदों के खरीद–फरोख्त के घोटाले को दक्षिणी देशों में भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण कहकर नहीं टाला जा सकता। यह विदेशी कर्जदाताओं के निजीकरण के पक्ष में सशक्त दबाव का परिचायक है। रिश्वतखोरी के इस घोटाले में एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की सीधी भूमिका स्पष्ट नजर आती है। एडीबी ने खुद ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में कार्यरत अपने कर्मचारियों और क्रियान्वयन एजेंसियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 55 मामलों के जांच की बात स्वीकार की है। (बेल्लो : 2000)।

जहां तक लोकतांत्रिक फैसलों का सवाल है तो सरकारों के पास उदारीकरण के संभावित प्रभावों की समुचित जानकारी नहीं होती। नीदरलैंड में एंडेसा के प्रयासों के एक ताजे अध्ययन में पाया गया कि आइधोवन शहर की नगरपालिका को एंडेसा के साथ अनुबंध के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया जबकि उनके पास न तो कंपनी के बारे में कोई जानकारी थी और न ही निजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। कंपनी की कोई भी प्रोफाइल उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई और सौदे की जिम्मेदारी जिन सांसदों पर थी उन्होंने अपने आप मान लिया कि इससे बिजली के दामों में कमी आएगी और सबकी नौकरियां भी बरकरार रहेंगी। लेकिन एंडेसा की अपनी रणनीति स्पष्ट थी। इसका इरादा 2001 और 2003 के दौरान अपने कुल कर्मचारियों की संख्या 13.6 प्रतिशत कम करने का था और उसने लैटिन अमरीका में सितंबर 2000 से सितंबर 2001 के दौरान ही 6.8 प्रतिशम कर्मचारियों की छंटनी कर दी। (वांडर स्टिचेले : 2002)।

सरकारें निवेशकों को लुभाने के लिए या कर्जदाताओं की शर्तें पूरी करने के लिए इन कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा रियायतें देती हैं। इन रियायतों में करों में विशेष छूट शामिल है। एईएस ने होंडुरास की सरकार से बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए पूर्ण मुक्त व्यापारिक क्षेत्र की रियायतों की मांग की। इसी कंपनी ने उगांडा सरकार से अतिरिक्त बिजली संयंत्र के निर्माण के दौरान दिए गए मूल्य युक्त कर (वैट) के तुरंत भुगतान की मांग की। (बेलिस : 2002)।

अपने सारे प्रयासों के बावजूद विदेशी कंपनियां दक्षिणी देशों की

सरकारों पर दबाव बनाने में हमेशा ही कामयाब नहीं होतीं। स्थानीय नगरपालिकाओं के प्रबल प्रतिरोध तथा संवैधानिक न्यायाधिकरण के नकारात्मक फैसले के चलते बोली लगाने की पात्रता वाली कंपनियों– स्पेन की यूनियन फेनोसा, अमरीकी एईएस और अर्जेंटीना की पेकॉम के बोली लगाने से हट जाने के बाद, अप्रैल 2002 में इक्वाडोर की सरकार ने वितरण कंपनियों की बिक्री निरस्त कर दी। इसी प्रकार मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2002 में अपने एक फैसले से राष्ट्रीय बिजली बाजार और विनियंत्रण तथा इलेक्ट्रिसिटी द फ्रांस और स्पेनी कंपनियों इबरद्रोला एवं यूनियन फेनोसा की विस्तार योजनाओं पर रोक लगा दी। (अज़नारेज : 2002)।

मिथक–6

निजीकरण और विनियंत्रण गरीबों के लिए लाभप्रद

स्थिर विकास पर विश्व शिखर–वार्ता (डब्लूएसएसडी) की तीसरी तैयारी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के पैनल ने बताया कि दुनिया के 2 अरब लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, आधुनिक विद्युत सेवाओं से वंचित हैं। बैठक ने राय दी कि "यह दुनिया की सबसे अहम विकास की समस्या है"। उसने "राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर नीतियों में सामंजस्य बनाने" की अनुशंसा किया (गयात्रिइयर : 2002)। दुर्भाग्य से मुख्यधारा की एजेंसियों के परिप्रेक्ष्य से यह सामंजस्य नाकाम उदारीकरण की नीतियों पर आधारित है।

इन मुनाफाखोर कंपनियों का मकसद वंचित समूहों को बिजली उपलब्ध कराना नहीं है बल्कि इनका मकसद एक सुरक्षित और फायदेमंद बाजार की तलाश है। व्यापारिक कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के लिए खास उत्सुक नहीं हैं और बिजली की दर बढ़ाने की शर्त पर ही वे ऐसा करती हैं। ऐसा करने में सरकार की आर्थिक–सामाजिक नीतियों की धज्जियां उड़ जाएं तो उनकी बला से।

निजीकरण और विनियंत्रण के बावजूद समाज के सभी तबकों को बिजली मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। विकल्प सीमित है : सरकार या तो निजी कंपनियों को रियायत दे या फिर इन कंपनियों द्वारा वसूली जाने वाली दरों को प्रतिबंधित करे, जिसकी संभावना कम है। दरों का स्तर निश्चित रूप से एक राजनैतिक मसला है। 'उदारीकृत परिदृश्य में बिना

प्रतिस्पर्धा रहित माहौल के 'बाजार मूल्य' का कोई मतलब नहीं है (बेलिस 2001)।

विद्युत क्षेत्र के उदारीकरण का मध्य और पूर्वी यूरोप के तथाकथित संक्रमणकालीन समाजों पर विशेष प्रभाव पड़ा। एक तरफ रियायतों की समाप्ति से विद्युत सक्षम अभियांत्रिकी को प्रोत्साहन मिला जिससे पर्यावरण में कुछ सुधार हुआ। दूसरी तरफ रियायतों की समाप्ति से गंभीर सामाजिक समस्याएं पैदा हो गईं। बढती गरीबी के माहौल में बिजली के ऊंचे दामों के चलते समाज का एक बड़ा तबका बिजली की सुविधा से वंचित

बॉक्स–6
कनाडा : ओंटारिओ में जल संपदा के अपव्यय के मनमाने दाम।

कनाडियन स्टडी फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स के एक ताजे अध्ययन के अनुसार, ओंटारिओ के विद्युत क्षेत्र के निजीकरण से अब तक अरबों की सार्वजनिक संपदा लुटाई जा चुकी है। इससे बिजली के दाम बढ़ेंगे और सार्वजनिक सेवाओं के बजट में कमी आएगी। ओंटारिओ की विद्युत प्रणाली, हाइड्रो वन बिना जोखिम के विद्युत उत्पादन से पर्याप्त लाभ की स्थिति में है। 2000 और 2001 में इसने 95 करोड़ डॉलर (कनाडियन) मुनाफा कमाया और 2002 में इसमें इजाफे की अपेक्षा थी। मौजूदा दर से हाइड्रो वन की मौजूदा कीमत कम से कम 10 अरब डॉलर है और मुनाफे में बढ़ोत्तरी के साथ इसका दाम बढ़ता जाएगा। निआगरा फाल्स एवं प्रांत की अन्य जल विद्युत संपदाओं की कीमत कम से कम 16.7 अरब डॉलर है। हाइड्रो वन को मात्र 5.5 अरब डॉलर में बेचने की योजना थी।

सार्वजनिक संपदा की भारी घाटे पर बिक्री से केवल आर्थिक क्षति ही नहीं होगी, ओंटारिओ में बिजली की दर बढ़कर अमरीका में प्रचलित दरों के बराबर पहुंच जाएगी। उत्तरी अमरीका मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) के तहत अमरीकी कंपनियां कनाडा के बिजली बाजार में दखल दे सकती हैं। उनकी दखलअंदाजी पर केवल एक प्रतिबंध होगा। दक्षिणी भागों में विद्युत संचार को सुलभ बनाना। बाजार रणनीति का अनुपालन करते हुए हाइड्रो–वन अपनी क्षमता बढ़ाएगा और फलस्वरूप ओंटारिओ वासियों को बिजली के मद में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

बिना बिजली की दर बढ़ाए इस जल–संसाधन से लाभ कमाने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। इससे होने वाले लाभ का इस्तेमाल स्वास्थ्य–सुविधाओं, शिक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में किया जा सकता था जैसा कि कनाडा के क्यूबेक, मनीटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतों में सार्वजनिक विद्युत उपक्रमों से होने वाली आय को इन मदों में लगाया जा रहा है। लेकिन निजीकरण के बाद यह आय विदेशी निवेशकों की जेबों में चली जाएगी। फायदेमंद सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण "वैचारिक दिवालियापन, अक्षमता और जनहित की उपेक्षा का परिचायक है।" (गॉर्डन : 2002 : 1)।

बॉक्स–7

भारत : एनरॉन डाभोल विद्युत परियोजना पर विवाद

भारतीय राज्य, महाराष्ट्र में एनरॉन की डाभोल विद्युत परियोजना पर विवाद 10 साल से अधिक पुराना हो गया है। इन सालों में इस विवाद ने काफी उतार–चढ़ाव देखा। इस परियोजना में एनरॉन के अलावा दो अन्य अमरीकी कंपनियां – बेक्टेल और जनरल इलैक्ट्रिक भी शरीक हैं।

डाभोल परियोजना भारत में पहली निजी एवं तरल प्राकृतिक गैस पर आधारित सबसे बड़ी विदेशी परियोजना थी। राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों ने एनरॉन के साथ बिजली खरीदने का समझौता (पीपीए) एवं अन्य समझौते किए जिसे काफी दिनों तक गुप्त रखा गया। जब लोगों को बिजली के ऊंचे दामों का पता चला और सरकार ने परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू किया तो लोगों ने संगठित होकर परियोजना स्थल एवं राज्य की अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। प्रभावित होने वाले समाज के तमाम तबके परियोजना के विरूद्ध तरह–तरह की गतिविधियों में जुट गए।

एनरॉन ने राज्य सरकार की मदद से विरोध को कुचलने का प्रयास किया। कंपनी के हेलीकॉप्टर समेत, एनरॉन के संसाधनों के इस्तेमाल से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का बर्बरतापूर्ण दमन किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मछुआरों के घरों में घुसकर बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक की पिटाई की।

परियोजना के पहले चरण में जब बिजली का उत्पादन शुरू हुआ तो कंपनी की हकीकत सामने आने लगी। अक्टूबर 2000 में सरकार ने खुद माना कि डाभोल एक 'सफेद हाथी' है। शुरू से ही स्पष्ट हो गया था कि एनरॉन का कुल सालाना भुगतान लगभग 1.3 अरब डॉलर होगा जबकि सार्वजनिक सेवा का कुल सालाना राजस्व मात्र 2.4 अरब रूपए था। यह भी स्पष्ट हो गया था कि एनरॉन की बिजली की कोई मांग ही नहीं थी।

राज्य सरकार ने एनरॉन को भुगतान की गारंटी का अनुबंध किया था लेकिन इसकी स्वयं की आर्थिक स्थिति काफी डांवाडोल थी। संक्षेप में कहें तो इस एक परियोजना ने सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकार को दिवालिएपन की कगार पर पहुंचा दिया। सरकार ने जब इस पर एनरॉन से बातचीत करना चाहा तो उसने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया। अंततः वामपंथी पार्टियों और जन–प्रतिरोध के दबाव में सरकार को बिजली खरीद समझौते (पीपीए) को निरस्त करना पड़ा। एनरॉन ने महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने मुंबई, दिल्ली और लंदन में कानूनी कार्रवाई शुरू की और बड़े स्तर पर विज्ञापन अभियान छेड़ा। इसने दो अमरीकी राष्ट्रपतियों और इंगलैंड के प्रधानमंत्री से भी दबाव डलवाया।

राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एनरॉन की गड़बड़ियों और परियोजना की मंजूरी के तरीकों में अनियमितताओं का विस्तृत

वर्णन किया है। आयोग ने पूरी प्रक्रिया को "व्यापक और सतत् शासन की असफलता" के रूप में चिन्हित किया। आयोग ने आगे कहा कि अलग–अलग पार्टियों के शासनकाल में राजनैतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में निरंतर ऐसी असफलता महज संयोग नहीं हो सकती, इसके लिए "नाजायज प्रभाव" के इस्तेमाल का सुनियोजित इस्तेमाल किया गया होगा। अनजाने में ही सही, एनरॉन ने खुद रिश्वत की बात कबूल की। अमरीकी संसदीय समिति को एनरॉन के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को "शिक्षित" करने में 6 करोड़ डॉलर खर्च किया था।

अमरीका में एनरॉन के ढहजाने के बाद भारत में इसके क्रिया–कलाप और भी संदिग्ध हो गए। कहा गया था कि एनरॉन देश में विदेशी पूंजी लगाएगा लेकिन कंपनी ने भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ही कर्ज लेकर परियोजना में लगाया। एनरॉन ने इन कर्जदाताओं से आंखमिचौली खेलना शुरू कर दिया। बिना कर्जदाताओं को सूचित किए इस संयंत्र से सूक्ष्म संशोधक मशीनें (माइक्रोप्रॉसेसर) निकाल ली गई। यह भी पाया गया कि बेक्टेल द्वारा लगाए गए नाफ्था भंडारण टंकियों से गैस लीक करती है। तमाम शिकायतों के बाद एनरॉन ने इसकी जांच के लिए अपने ही एक अधिकारी को लगा दिया। रिसाव से आसपास के कुएं प्रदूषित हो गए। इस जांच अधिकारी ने बताया कि इस पानी को पीने वाले अगले एक दशक में कैंसर के शिकार हो जाएंगे। एनरॉन इस रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई और अदालतों, सरकार और स्थानीय समुदाय को झूठी जानकारियां देती रही।

एनरॉन प्रकरण अभी खत्म नहीं हुआ है। आधिकारिक रूप से नियुक्त जांच आयोग ने अभी काम शुरू नहीं किया है। महाराष्ट्र को निजीकरण का मतलब समझ में आ गया है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि निजीकरण दक्षता और जनहित के लिए कोई रामबाण नहीं है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि बड़ी–बड़ी कंपनियां भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों से गठजोड़ करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसी भी अमानवीय हद को पार कर सकती हैं।

टीएनआई के सहभागी प्रयास की रिपोर्ट

हो गया। निजी कंपनियों की इस मुनाफाखोरी की तारीफ में विश्व बैंक ने कसीदे पढ़े। जॉर्जिया में एईएस के कामों के मूल्यांकन के संदर्भ में विश्व बैंक के अधिकारियों ने लिखा, "दोषी उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने का कंपनी का बुद्धिमानीपूर्ण तरीका काबिले–तारीफ है।" भुगतान के बकाया के लिए किसी खास अपार्टमेंट की बिजली काटना संभव नहीं था, इसलिए एईएस ने पूरे ब्लॉक की बिजली काटने का तरीका अपनाया। इसके बारे में विश्व बैंक ने कहा, "ऐसे तरीकों का कड़ाई से पालन करते हुए कंपनी ने बकायादारी को कम किया और बकाया वसूली में काफी प्रगति की।" जॉर्जिया की कड़कड़ाती ठंड में गरीबों को अपनी आय का 40 प्रतिशत बिजली के दाम के भुगतान

बॉक्स–8

दक्षिण अफ्रीका : सशक्त हाथ में ताकत – लेकिन जनता भी शक्तिशाली है

अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) के सार्वजनिक उपक्रम मंत्री जेफ रडाबे ने दिसंबर में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा, "यह एक अपराधी गिरोह है"। वे सोवेटो इलेक्ट्रिसिटी कमेटी (एसईसीसी) के कार्यकर्ताओं को उनके आपरेशन खानाइसा के लिए फटकार लगा रहे थे। ये कार्यकर्ता बिजली जोड़ो अभियान चला रहे थे। भारीभरकम बिजली के बिल का भुगतान करने में असमर्थ जनता ने छः महीने अंधेरे में रहने के बाद बिजली का अवैध इस्तेमाल शुरू किया। एसईसीसी के कार्यकर्ता बिना किसी शुल्क के लोगों की बिजली जोड़ने का खतरा उठा रहे थे।

दक्षिण अफ्रीका का सबसे अहम सार्वजनिक उपक्रम और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैर–पेट्रोलियम विद्युत उपक्रम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कमीशन (एसकाम)। निजीकरण की प्रक्रिया में यह दक्षिण अफ्रीका की सफलतम इकाई होने का दावा करती है। यह हर वर्ष दक्षिण अफ्रीका के 300,000 से अधिक घरों में बिजली प्रदान करती है। फिर भी हजारों परिवार ऐसे हैं जो 1998 में अपनाई गई पूरा दाम सधाने की नीति के तहत इसकी बिजली की दरों के भुगतान में अपने को असमर्थ पाते हैं। नवउदारवादी नीति के तहत बिल के भुगतान में असमर्थ लोगों की बिजली काट देना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि रंगभेद नीति के चलते अश्वेत अफ्रीकियों को 1980 के दशक तक वैसे भी एस्कॉम की सेवाएं नहीं मिलती थीं। 1951 से 1966 के बीच एस्कॉम ग्रिड के विस्तार के लिए 10 करोड़ डॉलर विश्व बैंक के कर्ज के बावजूद इसकी बिजली अश्वेत बस्तियों तक नहीं पहुंची और इसीलिए स्थानीय कार्यकर्ता बैंक से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नतीजतन कोयले और लकड़ी के कबाड़ की वजह से बस्तियों में गंदगी फैली रहती थी।

एस्कॉम विरोध का मुख्य निशाना बना हुआ है। इसने 1990 के दशक में 85,000 में से 40,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर ठेके पर काम कराना शुरू कर दिया। इससे कर्मचारी कंपनी से खफा हो गए। इसके अलावा एस्कॉम को पर्यावरणविदों का भी गुस्सा झेलना पड़ता है क्योंकि अत्यधिक कोयला जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए इसके पास सल्फर सोखने के उपकरण नहीं हैं। देश में हवा और सूर्य की रोशनी की प्रचुरता के बाद विद्युत के इन पुनरूपयोगी स्रोतों का इस्तेमाल नगण्य है। इन स्रोतों का इस्तेमाल न करके एस्कॉम परमाणु–ऊर्जा से संयंत्र चलाने की फिराक में है। ऐसा करने वाला इसका ब्रिटिश साझीदार लगभग दिवालिएपन की कगार पर है।

इसे रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका की विद्युत नीति के अवशेष के रूप में देखा जाता है और इसलिए बहुत से दक्षिण अफ्रीकी इसके आलोचक हैं। इसके सबसे प्रखर आलोचक हैं ट्रेवर नग्बाने जो सोवेटो से एएनसी के पार्षद रह चुके हैं और जिन्हें निजीकरण के विरोध के कारण पार्टी से निकाल दिया गया। नग्वाने के अनुसार, "हमारा मानना है कि गरीबों को और अधिक चूसने वाला निजीकरण का अभियान एस्कॉम में अत्यधिक असामाजिक और पर्यावरण विरोधी रणनीतियों का समागम

करने वाला है। हमारा विश्वास है कि दुनिया में निजीकरण के खिलाफ लहर चल पड़ी है। पुनर्राष्ट्रीयकरण अब जनोद्गार बन चुकी है।"

नग्वाने का कहना है कि ऑपरेशन खानाइसा एक सफल अभियान है। अक्टूबर 2002 में जनांदोलनों के दबाव में एस्कॉम को घोषित करना पड़ा कि भुगतान न कर सकने पर अब किसी की बिजली नहीं कटेगी। "एस्कॉम की इस पलट नीति का श्रेय जनता की ताकत को जाता है। पिछले साल हमने विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदारी के लिए हजारों–हजार छात्रों को लामबंद किया। हमने एस्कॉम की आलोचना के लिए बौद्धिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा अर्जित की और इसे विश्वविद्यालय की पढ़ाई के साथ जोड़ा।"

बांड (2002) से

के लिए देने को मजबूर होना पड़ा (कोचलाड्चे : 2001)।

इसी प्रकार के क्रूर, अमानवीय तरीके मोल्दोवा में भी अपनाए गए। स्पेनी कंपनी यूनियन फेनोसा ने 2000 में यहां के बिजली नेटवर्क का 60 प्रतिशत हिस्सा खरीद लिया और लोगों के घरों में विद्युत उपकरणों की अनिवार्य सूची लगा दी। ज्यादा उपकरण और बिजली का 'ज्यादा बिल' मजदूर आंदोलन के परिप्रेक्ष्य से यह मानवाधिकारों का हनन है। यूनियन फेनोसा के प्रवक्ता के अनुसार, "लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है, परोपकारी एजेंसी नहीं।" सोवियत संघ के विघटन के बाद जॉर्जिया में बिजली के दाम आसमान छूने लगे और बिजली एक बड़ी आबादी की पहुंच से दूर हो गयी। कुछ ने बिजली के इस्तेमाल में कटौती कर दी और कुछ ने मीटर रीडरों से सांठ–गांठ करके ग्रिड से सीधे बिजली लेना शुरू कर दिया (रेम्सफोर्ड : 2001)।

बिजली के बढ़ते और अस्थिर दरों से उत्तरी, धनी देशों के गरीबों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। अमरीका में निम्न आय–वर्ग का औसत परिवार कुल घरेलू आय का 19 प्रतिशत बिजली पर खर्च करता है। इनमें सबसे गरीब या एकल मां–बाप वाले परिवारों के लिए यह खर्च उनकी कुल आमदनी के 25 प्रतिशत से भी अधिक पड़ जाता है। बढ़ी दर से बिजली के बिल का भुगतान "भोजन व्यय में कटौती, किराया बकाया रखने या दवा के बिना रहने के बिना संभव नहीं है" (ऑपेनहाइम : 2001:13)।

लाभप्रद सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के चलते होने वाले

राजस्व के घाटे से राज्य द्वारा संचालित कई कार्यक्रमों को रियायतें दी जा सकती थीं। अफ्रीका में निजीकरण पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1996 तक अफ्रीका के उपसहारा क्षेत्र में 2700 सौदे हुए और जितनी कंपनियों का निजीकरण किया गया उनमें से कई मुनाफे में चलने वाली थीं (कैंपबेल, व्हाइट और भाटिया : 1998)। कनाडा और कोलंबिया में भी निजीकरण के चलते काफी राजस्व का घाटा हुआ। (बॉक्स–4 और 6)। यही कारण है कि व्यापारिक रूप से फायदेमंद सार्वजनिक कंपनियों के पक्ष में उरूग्वे की ट्रेड यूनियनों ने लंबे संघर्ष का रास्ता अपनाया और उन्हें इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। अपने संघर्षों के दौरान यूनियनों ने निजीकरण के खिलाफ रायशुमारी और जनमतसंग्रह के कई अभियान चलाये (एयूटीई : 2001)।

जहां तक रोजगार का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर परिसंघ आईसीईएम (रासायनिक, खनन और ऊर्जा) तथा पीएसआई (सार्वजनिक सेवा) ने उदारीकरण के चलते बेरोजगारी के कई सबूत पेश किए हैं। आईएलओ का एक विश्वव्यापी अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करता है। इसके अनुसार, "सार्वजनिक क्षेत्रों के ढांचागत समायोजन के साथ रोजगार में कमी अवश्यंभावी है– चाहे मामला निजीकरण का हो या योजनाओं के समायोजन का" (दि लुका : 1998 : xii)। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संभावित खरीदारों को लुभाने के लिए सरकारें निजीकरण के पहले भी कर्मचारियों की छंटनी कर सकती हैं। इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि "30 से 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों की छंटनी आम बात हो गई है" (xii)।

उपयोगी वेबसाइट

गैट्सवाच.आर्ग–क्रिटिकल इंफो ऑन गैट्स
http://www.gatswatch.org/

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कैमिकल, एनर्जी, माइन एंड जनरल वर्कर्स यूनियन (आईसीईएम)
http://www.icem.org/

पॉवर टू द पीपुल
http://www.powertothepeople.org/

पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल
http://www.world-psi.org/

पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल रिसर्च यूनिट
http://www.psiru.org/

पब्लिक सिटीज़ंस क्रिटिकल मास एनर्जी एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम
http://www.citizen.org/cmep/

सस्टेनेबल एनर्जी एंड इकॉनोमी नेटवर्क
http://www.seen.org

द एनर्जी प्रोजेक्ट
http://www.tni.org/energy (इसमें वेबसाइट में सहयोगी देशों– कैमरून, कोलम्बिया, भारत, इंडोनेशिया, उरूग्वे तथा पूर्वी यूरोप के लिंक भी शामिल हैं)

भूमंडलीय स्तर पर बिजली के उदारीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कॉरपोरेटी सुधारों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और बहुआयामी विकास बैंक दक्षता सुधारने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के माध्यम के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर देश बिजली क्षेत्र के निजीकरण और विनियंत्रण की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसा वे प्रायः विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता एजेंसियों की शर्तों के दबाव में कर रहे हैं।

यदि निजीकरण और विनियंत्रण की प्रक्रिया का मकसद कार्यक्षमता बढ़ाना और कम दाम पर बिजली मुहैया कराना है तो यह इसमें बिल्कुल नाकाम रही है। पिछले 5 सालों में न्यूजीलैंड से कैलीफोर्निया और भारत से ब्राजील तक बिजली गुल होना, दामों का बढ़ना, पर्यावरण प्रदूषण और भ्रष्टाचार की कहानियां उदारीकरण का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं।

बिजली और समाज का यह पहला अंक उदारीकरण के फायदों के वायदों से परे दुनिया भर में फैले निजीकरण और विनियंत्रण के मिथकों की हकीकत उजागर करने का एक प्रयास है।

पीस
पॉपुलर एजूकेशन एंड एक्शन सेंटर
एफ–93, प्रथम तल, कटवारिया सराय
नई दिल्ली–110016, इंडिया
टेलफैक्स: 91–11–26968121 / 26858940
email: peaceact@vsnl.com